आज श्रीमन्, स्थिति यह हो गई है कि फसल ही खराब नहीं हुई है, गरीबों के मकानों के खपड़े तक चूर-चूर हो गए हैं। उनके पास रहने को छाया तक नहीं रही है। यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है और इसकी ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान जाना चाहिए और फौरन इसके लिए सहायता पहुंचानी चाहिए। अभी जो उनसे तकाबी की वसूली हो रही है, इसको रोका जाना चाहिए। जब उनके पास आज खाने को नहीं है तो वे इस कर्ज का भुगतान कैसे कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश में इस ओला-वृष्टि से भयंकर अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई। समूचा मध्य प्रदेश इसकी चपेट में है। इसलिए मैं चाहूंगा कि केन्द्रीय सरकार इसमें रुचि ले। अब यह केवल राज्य का ही कार्य नहीं रह गया है। समूचे देश की जनता को, मध्य प्रदेश की जनता की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। इस भयंकर ओला-वृष्टि में पशु मर गये, लोगों के मकान ढह गये और उनकी फसलें नष्ट हो गयीं। इसलिए श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि पुराने कर्जों की जो वसूली की जा रही है इसे फौरन रोका जाना चाहिए। यही नहीं अगर उन्हें खाद्य के लिए, बीज के लिए और सहायता नहीं दी जाएगी तो आगे अनाज पैदा होने वाला नहीं है। वर्तमान रबी फसल के लिए जो खाद और बीज की तकाबी दी गई थी उसे माफ किया जाना चाहिए क्योंकि वह फसल 50 प्रतिशत चौपट हो गई है।

मध्य प्रदेश के लोगों से इस विपदा में न केवल कर्जों की वसूली न की जाए बल्कि हर पंचायत में उनके लिए राहत कार्य भी शुरू किये जाएं और युद्धस्तर पर शुरू किये जाएं जिससे कि उन्हें जिनके पास पैसा नहीं है, कोई काम नहीं हैं, अनाज मिल सके। यहां तक कि मुफ्त भोजन का भी इंतजाम उन लोगों के लिए होना चाहिए जो वृद्ध, अशक्त और निराश्रित हैं।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से, प्रधान मंत्री जी से और केन्द्रीय शासन से अनुरोध करूंगा कि वह इस महान विपदा में मध्य प्रदेश की सहायता करें और प्रधान मंत्री सहायता कोष से तथा भारत सरकार के आपत्कालीन कोष से मध्य प्रदेश की जनता को सहायता पहुंचाएं।

MR. SPEAKER: Shri Laxmi Narain Nayak. The same thing should not be repeated because the hon. Member has already covered the whole thing.

(iv) REPORTED DAMAGE TO STANDING CROPS BY HAIL STROM IN CHHATTARPUR DISTRICT OF KHAJURAHO, MADHYA PRADESH

श्री लक्ष्मी नारायण नायक: (खजुराहो): श्रीमन्, मैं नियम 377 के अधीन मध्य प्रदेश में जो ओला-वृष्टि हुई है, उस की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में यह ओलावृष्टि हुई है। खास कर खजुराहो के टीकमगढ़ व छतरपुर जिलों में तो इतने भारी ओले पड़े हैं कि वहां के मकानों में उनके निशान इस तरह से दिखाई देते हैं जैसे कि गोलियों के निशान हों। वहां के लोगों की फसल नष्ट हो गई है, मवेशी मर गये हैं। फसल तो इस तरह से चौपट हुई है कि कोई फसल दिखाई ही नहीं देती। इसके कारण वहां के मजदूर और किसान चौपट हो गए हैं। आज वे लोग दाने दाने को मोहताज बन गये हैं।

इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में वहां के लोगों को केन्द्रीय सरकार को भी सहायता करनी चाहिए, मध्यप्रदेश की सरकार तो करेगी ही। जब केन्द्रीय सरकार सहायता करेगी, तभी लोगों का संकट दूर हो सकता है। जब तक यह सहायता उन्हें नहीं दी जाती तब तक वे आगे की फसल कैसे दे सकते हैं। आज उन्हें खाद की जरूरत है, बीज की जरूरत है, चारे की जरूरत है। पहले तो किसानों

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

ने खाद उधार ले लिया था, बीज उधार ले लिया था। आज यह जरूरी हो गया है कि सरकार उन लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता पहुंचाए जिससे कि वे फसल बो सकें। नहीं तो वे अगली गर्मी की फसल नहीं बो पायेंगे। इसलिए सरकार को उन लोगों की अधिक से अधिक सहायता करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

उन लोगों के लिए राहत कार्य भी तत्काल शुरू करने की जरूरत है। इस क्षति में वहां के खेतिहर मजदूरों के पास क्रय शक्ति नहीं रही है। उन्हें गल्ले पहुंचाने की जरूरत है जिससे वे अपना जीवन बचा सकें। मध्य प्रदेश के कई जिलो—सीहोर, विदिशा, दमोह, सागर, रायसेन, सतना, रीवा—में इस ओला वृष्टि से क्षति हुई है। अकाल एरिया घोषित कर तत्काल सहायता की जाये। वहां की जनता का कष्ट दूर हो इसके लिए मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार तुरन्त उनकी सहायता करे और जो संकट आया है वह दूर हो सके, इसके उपाय करे।

(v) NEED FOR CENTRAL ASSISTANCE TO MADHYA PRADESH TO MEET THE SITUATION ARISING OUT OF HEAVY RAINS

श्री निर्मल चन्द्र जैन (सिवनी) : इसी प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान दिलाते हुए आगे की कुछ और बातें कहना चाहता हूं। वहां पर असमय वर्षा हुई है, बहुत हुई है। जबलपुर और सिवनी जिले में 85 इंच तक वर्षा इस बार हुई है। उसके कारण दो-दो बार दौनीं करनी पड़गी किसानों को। दो बार करने के बाद जब फसल लहलहा रही थी तब ओला-वृष्टि हो गई और जबलपुर और सिवनी तथा मध्य भारत के बहुत से जिले उससे प्रभावित हुए और इसने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। पिछली बार मध्य प्रदेश सरकार को 35 करोड़ रुपया राहत कार्यों पर खर्चा करना पड़ा था जिस में से केन्द्रीय सरकार ने केवल पांच करोड़ दिया और तीस करोड़ उसे अपने खाते से खर्च करना पड़ा। अब जो राहत कार्य हाथ में लिए जाएंगे उनमें मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा अंशदान दें। इस बात की बहुत आवश्यकता है कि तकाबी की जो वसूली की जा रही है उसे तुरन्त निरस्त कर दिया जाए। बैंक लोंज पर जो ब्याज है वह माफ कर दिया जाना चाहिए। बैंकों की तरफ से किसानों से आगे कर्जा वसूल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आदेश तो कम से कम केन्द्रीय सरकार उनके दे ही सकती है।

वहां इस समय फसल बिल्कुल चौपट हो चुकी है। अन्न तथा धन से तत्काल मध्य प्रदेश की इस संकट की घड़ी में सहायता की जानी चाहिए। उसी तत्परता के साथ सहायता की जानी चाहिए जिस तत्परता के साथ आंध्र और तमिलनाडु में हुई क्षति को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने सहायता की थी। उसी तत्परता के साथ मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्र की ओर से अंशदान भी दिया जाए और अन्न सहायता भी प्रदान की जाए।

12.40 hrs.

INTEREST BILL—*contd.*

MR. SPEAKER: Now, we take up next item. Mr. Patel....

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): Sir......

MR. SPEAKER: Mr. Venkataraman, you want to object to it at this stage?